



18 मिनट	8	23	5 + 1	GS2 • 17	GS3 • 14
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण	

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 भारत ने माना कि कच्छेतीवु श्रीलंका का है

क्यों जरूरी: समुद्री सीमा और क्षेत्रीय अखंडता: GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय अध्ययन का एक प्रमुख विषय।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

2 भारत और फ्रांस जल और तापमान की निगरानी के लिए त्रिशना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे

क्यों जरूरी: संसाधन प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष-आधारित रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing): GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भूगोल का एक केस स्टडी।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

3 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में कई

क्यों जरूरी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने व्यापार स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को बढ़ाने और दंड को कम करने का निर्णय लिया है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

4 अमेरिका ने संपत्तियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए

क्यों जरूरी: अंतरराष्ट्रीय संबंध और कानून का शासन: बहुपक्षीय न्यायिक निकायों (Multilateral Judicial Bodies) पर एकपक्षीय प्रतिबंधों का विश्लेषण।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

5 स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के आदेश के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किए

क्यों जरूरी: मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कार्यकारी आदेशों की न्यायिक समीक्षा: एक GS2 पॉलिटी केस स्टडी।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

स्टैटिक से जोड़ें

Section 163 BNSS

वह प्रावधान जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास निषेधात्मक आदेश (prohibitory orders) जारी किए जाते थे। खबर में: स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के आदेश के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किए।

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

भारत ने माना कि कच्छेतीवू श्रीलंका का है

चर्चा में क्यों: श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि नई दिल्ली कच्छेतीवू द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा मानती है। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 1974 और 1976 के समझौतों पर दिए गए रुख का उल्लेख किया।

याद रखें

- कच्छेतीवू — एक द्वीप क्षेत्र जिसे भारत द्वारा श्रीलंका का हिस्सा माना गया है।
- 1974 और 1976 के समझौते — विशिष्ट समुद्री समझौते (maritime agreements) जिन्हें भारत ने दोबारा खोलने से इनकार कर दिया है।
- अनुर कुमार दिसानायके — नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन से श्रीलंका के प्रेसिडेंट।

मेन्स कोण भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्थिरता बनाए रखने और लघु-स्तरीय (आर्टिसनल) मछली पकड़ने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समुद्री सीमा समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134494

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

भारत और फ्रांस जल और तापमान की निगरानी के लिए त्रिशना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे

चर्चा में क्यों: URSC ने घोषणा की है कि जल संसाधनों और सतह के तापमान की निगरानी के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत विकसित TRISHNA सैटेलाइट को अगले 12-16 महीनों में लॉन्च किया जाएगा।

याद रखें

- TRISHNA: हाई-रिज़ॉल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट (Natural Resource Assessment) के लिए थर्मल इन्फ्रा-रेड इमेजिंग सैटेलाइट।
- CNES: फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी जो ISRO के साथ सहयोग कर रही है।
- TRISHNA, Megha-Tropiques और SARAL के बाद ISRO और CNES के बीच तीसरा जॉइंट प्रोजेक्ट है।

मेन्स कोण त्रिशना (TRISHNA) मिशन जैसी अंतरिक्ष-आधारित सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) प्रौद्योगिकियां भारत के जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134491

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में कई

चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने व्यापार स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को बढ़ाने और दंड को कम करने का निर्णय लिया है।

याद रखें

- GST उल्लंघन के लिए प्रॉसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- GST पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
- ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए लेट फीस माफी लागू होगी।

मेन्स कोण GST काउंसिल द्वारा दंड को कम करने और अभियोजन की सीमा (prosecution thresholds) को बढ़ाने के हालिया उपायों का विश्लेषण कीजिए कि ये कदम भारत में कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से कैसे कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134467

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

अमेरिका ने संपत्तियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी संपत्ति को ब्लॉक कर दिया गया है और उसके कामकाज को खतरे में डाल दिया गया है। इस कदम के बाद EU और स्टेट पार्टीज से न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की जा रही है।

याद रखें

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) — एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था जिस पर US के प्रतिबंध लगे हैं।
- Sanctions Regime — ICC के खिलाफ एसेट ब्लॉकिंग (asset blocking) और ऑपरेशनल खतरों (operational threats) सहित के उपाय।
- 180-दिन की ग्रेस पीरियड (grace period) — अमेरिकी उपायों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा।

मेन्स कोण अंतर्राष्ट्रीय न्याय और वैश्विक कानून के शासन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों पर लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134419

स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के आदेश के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किए

चर्चा में क्यों: एक स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के उस आदेश के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC के चेयरमैन को नोटिस जारी किए हैं, जो आवाजाही और इंटरनेट एक्सेस से संबंधित था।

याद रखें

- Section 163 BNSS: वह प्रावधान जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास निषेधात्मक आदेश (prohibitory orders) जारी किए जाते थे।
- प्रोहिबिटरी ज़ोन (Prohibitory zone): मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर सहित एक चार-किलोमीटर का ज़ोन, जहाँ डिटेंशन (detentions) पर रोक लगा दी गई थी।
- जंतर मंतर: मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल।

मेन्स कोण स्वतंत्र आवाजाही के मौलिक अधिकार को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति के बीच न्यायिक संतुलन के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134400

NASA और स्टारफिश स्पेस ने निष्क्रिय वस्तुओं तक पहुँचने के लिए SSPICY मिशन लॉन्च किया

चर्चा में क्यों: NASA और Starfish Space ने सैटेलाइट की मरम्मत और मलबे को हटाने के लिए स्वायत्त प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस (autonomous proximity operations) और रोबोटिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए SSPICY मिशन लॉन्च किया है।

याद रखें

- SSPICY: Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability मिशन।
- Otter स्पेसक्राफ्ट: इसे लो अर्थ ऑर्बिट (low Earth orbit) में स्थित चार निष्क्रिय अमेरिकी ऑब्जेक्ट्स के पास स्वायत्त रूप से (autonomously) पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस: SSPICY मिशन के लिए लॉन्च साइट।

मेन्स कोण अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौतियों और अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे की स्थिरता के समाधान में स्वायत्त अंतरिक्ष रोबोटिक्स के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134245

केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड चालू करने का निर्देश दिया

चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) को चालू करने का निर्देश दिया है और यह फैसला सुनाया है कि डिजी यात्रा (Digi Yatra) आधार विवरण अनिवार्य नहीं कर सकती।

याद रखें

- Digital Personal Data Protection Act, 2023: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाला कानून।
- डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023 के तहत स्थापित नियामक संस्था।
- डिजी यात्रा (Digi Yatra): फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) पर आधारित एक सहज यात्रा पहल।

मेन्स कोण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134313

US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने इंफोसिस और TCS को PERM प्रोग्राम से निलंबित किया

चर्चा में क्यों: अमेरिकी श्रम विभाग (Department of Labor) ने इंफोसिस और TCS सहित आठ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है।

याद रखें

- PERM: यह US Department of Labor द्वारा मैनेज किया जाने वाला Permanent Labor Certification प्रोग्राम है।
- पिछले साल के PERM सर्टिफिकेशन में भारतीय फर्मों की हिस्सेदारी 2% से कम रही।
- TCS की योजना पांच साल की अवधि में 15,000 US वर्कर्स को काम पर रखने की है।

मेन्स कोण अमेरिकी बाजार में भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं के परिचालन मॉडल पर श्रम प्रमाणन नियमों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134249

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

VPT स्कीम: तमिलनाडु ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए Vettri Payanam Thittam का विस्तार किया।

मतदाता की अपील: पश्चिम बंगाल में 19 में से 3 अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunals) में रिक्तियों के कारण 37 लाख वोटर अपीलें लंबित हैं।

ECI की नियुक्ति: राजस्थान-कैडर अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को 8 अप्रैल, 2030 तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (Deputy Election Commissioner) नियुक्त किया गया है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और इंटरनेट बंद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

UN की प्रतिक्रिया: भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ आत्मरक्षा की कार्रवाई का बचाव किया और UN Resolution 1540 और सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का हवाला दिया।

अस्पताल पर जुर्माना: NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट ने AI के जरिए पकड़ी गई अनियमितताओं और डुप्लिकेट बिलिंग के लिए 203 अस्पतालों पर ₹34.39 करोड़ का जुर्माना लगाया।

BNSS सेक्शन 163: सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध प्रदर्शनों के दौरान बैरिकेड्स हटाने और Section 163 हटाने का आदेश दिया।

अग्निवीर भर्ती: हरियाणा कैबिनेट ने विशेष विभागों के लिए ग्रुप-C परीक्षाओं और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Tests) से पूर्व-अग्निवीरों को छूट दी है।

तरंग शक्ति-2026: जोधपुर में आयोजित एक्सरसाइज के दौरान जर्मन और फ्रेंच जनरलों ने IAF की ऑपरेशनल क्षमताओं की प्रशंसा की।

रियाद एयरपोर्ट स्ट्राइक: भारत ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले की निंदा की, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए।

F-35 जेट की बिक्री: Tarang Shakti-2026 एक्सरसाइज के दौरान US ने भारत को F-35 जेट्स बेचने के लिए कोई आधिकारिक ऑफर नहीं दिया।

जाति डेटा कलेक्शन: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि प्राइवेट एम्प्लॉयर्स और संस्थान अनिवार्य रूप से जाति का विवरण नहीं मांग सकते।

आरक्षण कैप: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों में SC, ST और BC के लिए आरक्षण की सीमा 50% तय की है।

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

AI का प्रभाव: भारत में रूटीन ऑटोमेशन प्रेशर (Routine automation pressure) 2012 और 2025 के बीच 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया।

दुर्गा ई-ऑटो स्कीम: दिल्ली सरकार 13 जिलों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो प्रदान करेगी।

PRLS मूल्यांकन: यूनिन जल शक्ति मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल के फैसलों के लंबित होने के कारण पालमरू-रंगरेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (Palamuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme) के अप्रैजल (appraisal) को टाल दिया है।

LSI स्कीम: आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग (Horticulture Department) ने El Niño के कारण होने वाले हीट स्ट्रेस (heat stress) से बागों को बचाने के लिए एक योजना शुरू की।

लैंसेट कमीशन: 2100 तक मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले 17 प्रमुख खतरों की पहचान की गई है, जिनमें न्यूक्लियर वॉर (Nuclear War) और AI का दुरुपयोग शामिल है।

LHC अपग्रेड: CERN, कोलिजन रेट्स (collision rates) को दस गुना बढ़ाने के लिए Large Hadron Collider को High Luminosity LHC में अपग्रेड कर रहा है।

एल नीनो का पूर्वानुमान: NOAA ने दिसंबर 2026 तक एक बेहद मजबूत El Niño के आने की 100 प्रतिशत संभावना जताई है।

परीक्षा की ईमानदारी: कमेटी ने सार्वजनिक परीक्षाओं (Public Examinations) के लिए रैलियों को प्रतिबंधित करने और अंडरटेकिंग (undertakings) के माध्यम से देर से प्रवेश की अनुमति देने के लिए Public Examinations Act में संशोधन का सुझाव दिया है।

CREAMS बुलेटिन: 15 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2026 के बीच 7 राज्यों में फसल अवशेष जलाने की 287 घटनाएं दर्ज की गईं।

नोबेल पुरस्कार 2026: ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) में खोजों के लिए कार्ल डीसेरोथ (Karl Deisseroth), पीटर हेगेमैन (Peter Hegemann) और जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) को सम्मानित किया गया।

1 भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा (maritime boundary) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत इस बात को स्वीकार करता है कि कच्छथीवू (Katchatheevu) श्रीलंका का हिस्सा है।
2. अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं।
3. 1974 और 1976 के समुद्री समझौते (maritime agreements) नई दिल्ली द्वारा दोबारा खोले जाने के अधीन हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

2 TRISHNA सैटेलाइट मिशन पर ISRO के साथ कौन सी स्पेस एजेंसी सहयोग कर रही है?

- (a) जाक्सा (b) NASA
(c) ESA (d) CNES

3 अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा US प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए निर्धारित ग्रेस पीरियड (grace period) की अवधि क्या है?

- (a) 90 दिन (b) 180 दिन
(c) 365 दिन (d) 60 दिन

4 सेंट्रल दिल्ली में निषेधात्मक आदेशों (prohibitory orders) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रोहिबिटरी ज़ोन (Prohibitory zone) को सुप्रीम कोर्ट से पांच किलोमीटर के रेडियस तक बढ़ा दिया गया।
2. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अनिश्चित काल तक इंटरनेट ब्लैकआउट (internet blackout) बनाए रखने का आदेश दिया।
3. BNSS की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश (prohibitory orders) जारी किए गए थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

5 भारत में Data Protection Board की स्थापना के लिए कौन सा विधायी अधिनियम (legislative act) रूपरेखा प्रदान करता है?

- (a) पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 (b) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023
(c) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (d) इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS2 • अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्थिरता बनाए रखने और लघु-स्तरीय (आर्टिसनल) मछली पकड़ने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समुद्री सीमा समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

(9) 5 (10) 7 (11) 8 (12) 2 (13) 1 • 2026



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + वीडियो • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।